



LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Wednesday, November 27, 2024 / Agrahayana 6, 1946 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, November 27, 2024 / Agrahayana 6, 1946 (Saka)

<u>CONTENTS</u>	<u>PAGES</u>
ORAL ANSWER TO STARRED QUESTION (S.Q. NO. 21)	1 – 30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 22 – 40)	31 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 231 – 460)	51 – 280



सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Wednesday, November 27, 2024 / Agrahayana 6, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, November 27, 2024 / Agrahayana 6, 1946 (Saka)

<u>C O N T E N T S</u>	<u>P A G E S</u>
RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
PAPERS LAID ON THE TABLE	281 - 99
ASSENT TO BILLS	300
ELECTIONS TO COMMITTEES	300 - 02
(i) COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES	300
(ii) COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES	301
(iii) SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY, TRIVANDRUM	302
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	303 - 16
Shri Vishweshwar Hegde Kageri	303
Shri Bhartruhari Mahtab	304
Shri Gopal Jee Thakur	304
Shri Anurag Sharma	305
Shri Bidyut Baran Mahato	305
Shri Pradeep Purohit	306
Dr. Nishikant Dubey	306

Shri Yogender Chandolia	307
Shri Vishnu Dayal Ram	307
Shri P.P. Chaudhary	308
Shri Bibhu Prasad Tarai	308
Shri Gaurav Gogoi	309
Shri Pradyut Bordoloi	309
Shri Vamsi Krishna Gaddam	310
Shri Kodikunnil Suresh	310
Shri Rahul Kaswan	311
Dr. Shashi Tharoor	311
Shri Rajeev Rai	312
Shri Devesh Shakya	312
Shri Tharaniventhan M.S.	313
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	313
Shri Shrirang Appa Chandu Barne	314
Shrimati Shambhavi	314
Dr. Rajkumar Sangwan	315
Shri Amra Ram	315
Shri Joyanta Basumatary	316

(1100/SJN/UB)

(प्रश्न 21)

... (व्यवधान)

1100 बजे

(इस समय श्री गौरव गोगोई, श्री बी. मणिकम टैगोर, श्री इमरान मसूद, सुश्री एस. जोतिमणि और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

... (व्यवधान)

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : महोदय, सोशल मीडिया पर जो भी कुछ दिखाई जा रहा है, उसने हमारे नैतिक मूल्यों और संस्कारों पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई है।... (व्यवधान) ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, वह बहुत अश्लील है, हम परिवार के साथ बैठकर उसको नहीं देख सकते हैं। उससे हमारे नैतिक मूल्यों का हास हुआ है। क्या सूचना और प्रसारण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रसारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूद तंत्र क्या है?... (व्यवधान)

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज्यादा प्रभावी नहीं है, क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है?... (व्यवधान)

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, वह विषय वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें पुराने कई जो डेमोक्रेटिक संस्थान थे और प्रेस का एक प्रकार था, जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज छप रही है, वह सही है या गलत है, उसको बारे में निर्णय लेकर मीडिया के अंदर लाया जाता था।... (व्यवधान) आज वह एडिटोरियल चेक खत्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के खत्म होने के कारण, आज जो सोशल मीडिया एक तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस का बहुत बड़ा माध्यम है, इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ यह एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन है, जिसमें कई तरह के वल्गार कंटेंट वगैरह भी आते हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है, उसको निश्चित तौर पर और कड़ा करने की जरूरत है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर एक कंसेंसस बने।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य सदन में पहली बार अपनी बात रख रहे हैं। वह नए सदस्य हैं। यह प्रश्न काल है। आप प्रश्न काल चलने दें। आपका जो विषय है, हम प्रश्न काल के बाद चर्चा करेंगे। आप प्रश्न काल चलने दें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं? क्या आप सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं? सदन मर्यादा से चले, सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर हो। आपको भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं तथा वे पहली बार प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सदन को चलने दें। आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर विराजें।

माननीय सदस्य, आप सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : महोदय, इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में विदेशी प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो भूमिका होती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को भारत के कानूनों के तहत जवाबदेह बनाने तथा इनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है?... (व्यवधान)

सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए। इससे हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी हिन्दू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको बहुत चोट पहुंचती है।... (व्यवधान) जब आज हम घरों में बैठकर टेलीविजन देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं, तो हम परिवार के साथ बैठकर वह नहीं देख पाते हैं। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से हास हुआ है। सरकार को पूरी तरह से इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए।... (व्यवधान)

(1105/YSH/SRG)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप शॉर्ट में जवाब दे दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री अश्विनी वैष्णव : मान्यवर अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। ... (व्यवधान) सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स जिन कंट्रीज से निकले हैं, वहां की संस्कृति और हमारे देश की संस्कृति में बहुत बड़ा फर्क है। ... (व्यवधान) इस तरह की डिबेट आज दुनिया के करीब-करीब हर देश में हो रही है, इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी इस विषय को उठाए। ... (व्यवधान) इस विषय पर समाज में सहमति हो तथा इस पर और कड़े कानून बनाए जाएं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल का समय महत्वपूर्ण है और यह आप सबका समय है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इसमें सरकार की जवाबदेही तय होती है। सरकार प्रश्नों पर जवाब देती है। आप प्रश्न काल को चलने दीजिए। आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि प्रश्न काल का समय महत्वपूर्ण है। आप सदन को चलने दीजिए। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। यह उचित नहीं है।

सभा की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1106 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/RAJ/RCP)

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत हुई।
(श्री दिलीप शङ्कीया पीठासीन हुए)

1200 बजे

(इस समय श्री अवधेश प्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर
पटल के निकट खड़े हो गए।)
... (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति (श्री दिलीप शङ्कीया) : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आइटम नम्बर – 2.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : राव इन्द्रजीत सिंह जी।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (RAO INDERJIT SINGH): On behalf of Shri Gajendra Singh Shekhawat, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2022-2023, together with Audit report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda for the year 2022-2023.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Buddhist Confederation, New Delhi for the year 2022-2023, along with audited accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Buddhist Confederation, New Delhi for the year 2022-2023.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.
- (5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958:-
 - (i) The National Monuments Authority Heritage bye-laws, 2024 of the Protected Monument – Bir Singh Palace at Datia, Madhya Pradesh.
 - (ii) The National Monuments Authority Heritage bye-laws, 2024 of Centrally Protected Monument – ‘Tomb of Shah Makhdum Daulah Maneri and Ibrahim Khan’ and ‘The Tank at Maner’, Maner, Patna, Bihar.
 - (iii) The National Monuments Authority Heritage bye-laws, 2024 of Centrally Protected Monument – ‘Karan Cheupar Cave’, ‘Sudama Cave’ and ‘Lomas Rishi Cave’, Barabar and Nagarjuni Hill, Jehanabad, Bihar.
 - (iv) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Protected Monument – ‘The tank and the remains at village Benisagar’, District – West Singhbhum, Jharkhand.
 - (v) The National Monuments Authority Heritage bye-laws, 2024 of the Protected Monument – Famous Temple Sacred to Mahasu (Hanol), Dehradun (Uttarakhand).
 - (vi) The National Monuments Authority Heritage bye-laws, 2024 of Centrally Protected Monument – Vapiyaka cave and

Vada Thika cave, Barabar and Nagarjuni hill, Jehanabad, Bihar.

- (vii) The National Monuments Authority Heritage bye-laws, 2024 of Centrally Protected Monument – Jageswar Group of Temples namely Jageswar, Mritunjaya, Nanda Devi, Shrine dedicated to Surya, Navagrah shrine, Pyramidal shrine, Kuber and Chandika Temples, Almora, Uttarakhand.
- (viii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Protected Monument – ‘The Asoka column known as Laur Pillar at Lauriya Areraj’, Govindganj, District – East Champaran, Bihar.
- (ix) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Protected Monument – ‘The Jamma Masjid at Hadaf’ and ‘Ruins of Baradari buildings with probable underground cells and passage standing on a high mound’, Village- Arazi Mukimpur, Rajmahal subdivision, Sahibganj, Jharkhand.
- (x) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Protected Monument – ‘Rangamati Mosque and the ablution tank attached thereto’, Rangamati hill, District- Dhubri, Assam.
- (xi) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Centrally Protected Monument – Tomb of Nadir Shah and Dome of Adil Shah Faruki, Burhanpur, Madhya Pradesh.
- (xii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Centrally Protected Monument – Gopi Cave, Barabar hill and Nagarjuni hill, Jehanabad, Bihar.
- (xiii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Protected Monument – ‘Excavated remains of stupa together with adjacent land comprised in whole of survey plot Nos. 261, 262, 263, 264,265,268, 269, 270 of village Harpur Basant and 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045,

- 1046, 1047, 1048 and 1049, of village Chakramdas', Harpur Basant and Chakramdas, District – Vaishali, Bihar.
- (xiv) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Centrally Protected Monument – 'The supposed site of the Palace of Asoka', Kumhrar, Patna, Bihar.
- (xv) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Protected Monument – 'Budhist Stupa', Tajpur Deur (Kesaria), District – East Champaran, Bihar.
- (xvi) The National Monuments Authority Heritage bye-laws, 2024 of Centrally Protected Monument – Sikandar Bagh Buildings and Monuments of the Ninety Third Highlanders, Lucknow, Uttar Pradesh.
- (xvii) The National Monuments Authority Heritage bye-laws, 2024 of Centrally Protected Monument – "Emperor Aurangzeb's Pavilion and Entire Compound Known as Bagh Badshahi, Tehsil – Khajuha, District - Fatehpur, Uttar Pradesh."
- (xviii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Protected Monument – Cemeteries near Kaiser Pasand, Lucknow, Uttar Pradesh.
- (xix) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Protected Monument – Tomb of Saadat Ali Khan, Tomb of Mashir Zaidi wife of Saadat Ali Khan and Sapper's Tomb, Kaisarbagh, Lucknow, Uttar Pradesh.
- (xx) The National Monuments Authority Heritage bye-laws, 2024 of Centrally Protected Monument – Dianut-ud-daula's Karbala situated in muhalla Menhadiganj, Lucknow.
- (xxi) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of the Protected Monument – Queen Victoria's Memorial in Alfred Park, Allahabad (Prayagraj), Uttar Pradesh.
- (xxii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Centrally Protected Monument – "Cemetery at Alambagh", Lucknow, Uttar Pradesh.

- (xxiii) The National Monuments Authority Heritage bye-laws, 2024 of Protected Monument – City Cemetery, Karwi, Village and Tehsil – Karwi, District Chitrakoot, Uttar Pradesh.
- (xxiv) The National Monuments Authority Heritage bye-laws, 2024 of Centrally Protected Monument – British Cemetery at Chiria Jhil, Lucknow.
- (xxv) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Protected Monument “Tomb of Nawab Sadar Jahan at Pihani in the Hardoi district, Uttar Pradesh.”
- (xxvi) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Protected Monument – One Ancient Brick Temple Built on the same plan as Bhitargaon Temple, Kanchilipur (Karchulipur), District – Kanpur, Uttar Pradesh.
- (xxvii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Protected Monument “Sai Bridge at second mile of the Raebareli and Pratapgarh Road, District-Raebareli, Uttar Pradesh”.
- (xxviii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Protected Monument “Heritage Bye-Laws for Cemetery at mile 6, (Lucknow, Cawnpore Road) Bagawan District-Lucknow, Uttar Pradesh”.
- (xxix) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Centrally Protected Monument- “Tomb of Ghazi-uddin Haider (First King of Oudh) in the Shah Najaf on the right bank of the river Gumti, Tehsil and District – Lucknow, U.P.”
- (xxx) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Centrally Protected Monument- Kacheri Cemetery, Kanpur, Uttar Pradesh.
- (xxxi) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Protected Monument “Cemetery at Marion, Tehsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh”.
- (xxxii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Protected Monument- Jami Masjid, East of Banda City, Near Hospital, Banda, Uttar Pradesh.

- (xxxiii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of Protected Monument- Kaisarbagh Gates, Lucknow, Uttar Pradesh.
- (xxxiv) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of the Protected Monument- “Jama Masjid situated within the village of Erich, Paragana Garotha, District- Jhansi, Uttar Pradesh”.
- (xxxv) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws, 2024 of the Protected Monument- Nasir-ud-Din Hiader’s Karbala at Daliganj, Tehsil Lucknow Sadar, District Lucknow, Uttar Pradesh.
- (xxxvi) The National Monuments Authority Heritage bye-laws, 2024 of the Protected Monument- Maqbara of Nawab Diler Khan a Distinguished Officer of Shah Jahan, Tehsil Shahabad, District Hardoi, Uttar Pradesh.
- (xxxvii) The National Monuments Authority Heritage Bye-laws 2024 of Protected Monument- The Tomb of Janab Aliya at Lucknow, Uttar Pradesh.

... (Interruptions)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) : माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 23 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 444(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 23 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 445(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 25 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 449(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 24 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 448(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 31 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 463(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2024 जो दिनांक 31 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 464(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 540(अ) जो 06 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 14 फरवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 99(अ) का एक शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (दो) सा.का.नि. 541(अ) जो 06 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 14 फरवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 98(अ) का एक शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 687(अ) जो 05 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम संघ-राज्यक्षेत्र, संयुक्त काडर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के लिए संयुक्त काडर प्राधिकरण गठित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) (एक) बीरबल साहनी पुरावनस्पतिविज्ञान, लखनऊ के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बीरबल साहनी पुरावनस्पतिविज्ञान, लखनऊ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान, बंगलोर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान, बंगलोर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालुर्जी एंड न्यू मेटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालुर्जी एंड न्यू मेटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) सत्येन्द्रनाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइन्सेज, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सत्येन्द्रनाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइन्सेज, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) (एक) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, अहमदाबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, अहमदाबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, शिलोंग के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, शिलोंग के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson, Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Jayant Chaudhary, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad (STARS), Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad (STARS), Mumbai, for the year 2021-2022.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3) (i) A copy each of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha, (STARS Scheme) Himachal Pradesh, Shimla, for the years 2020-2021 and 2021-2022.
- (ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha (STARS Scheme), Himachal Pradesh, Shimla, for the year 2020-2021 and 2021-2022.
- (4) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.
- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha, Gujarat Council of School Education, Gandhinagar, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha, Gujarat Council of School Education, Gandhinagar, for the year 2022-2023.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha, Tamil Nadu, Chennai, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha, Tamil Nadu, Chennai, for the years 2022-2023.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.
- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha, Chhattisgarh, Raipur, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha, Chhattisgarh, Raipur, for the year 2022-2023.
- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.
- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha, Andhra Pradesh, Vijayawada, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha, Vijayawada, Andhra Pradesh for the year 2021-2022.
- (12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.
- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha, U.P. Education for all Project Board, Lucknow, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the U.P. Education for all Project Board, Lucknow, for the year 2022-2023.
- (14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

- (15) (i) A copy each of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha, Maharashtra Prathamik Shiksha Parishad, Mumbai, for the years 2021-2022 and 2022-2023.
- (ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha, Maharashtra Prathamik Shiksha Parishad, Mumbai, for the years 2021-2022 and 2022-2023.
- (16) Two Statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.
- (17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the School Education Society, Himachal Pradesh, Samagra Shiksha, Shimla for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the School Education Society, Himachal Pradesh, Samagra Shiksha, Shimla, for the year 2022-2023.
- (18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I rise to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (1) Review by the Government of the working of the Indian Renewable Energy Development Agency Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.
- (2) Annual Report of the Indian Renewable Energy Development Agency Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE;
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY
AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson, Sir, with your
kind permission, on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, I rise to
lay on the Table :-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions)
under sub-section (4) of Section 19 of the Banking Companies
(Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts, 1970:-
 - (i) The Union Bank of India (Employees') Pension
(Amendment) Regulations, 2024 published in Notification
No. UBI:HR:16061(E) in Gazette of India dated 28th August,
2024.
 - (ii) The Indian Overseas Bank (Employees') Pension
(Amendment) Regulations, 2024 published in Notification
No. HRMD/PEN/001/2024 in Gazette of India dated 10th
September, 2024.
 - (iii) The Indian Bank (Employees') Pension (Amendment)
Regulations, 2024 published in Notification No. F. No.
Pen/01/2024(E) in Gazette of India dated 12th October,
2024.
 - (iv) The Bank of India (Employees') Pension (Amendment)
Regulations, 2024 published in Notification No.
HO:HR:TBD:2024-25:01(E) in Gazette of India dated 25th
September, 2024.
- (2) A copy of the 54th Valuation Report (Hindi and English versions) of
the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, as on 31st March,
2024.
- (3)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of
the Life Insurance Corporation of India, Mumbai, for the
year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the
Government of the working of the Life Insurance
Corporation of India, Mumbai, for the year 2023-2024.

- (4) A copy of the State Bank of India Employees' Pension Fund (Second Amendment) Regulations, 2024 (Hindi and English Versions) published in Notification No. HR/P&PMD/SPL/SP/2024-25/7 in Gazette of India dated 4th November, 2024 under sub-section (4) of Section 50 of the State Bank of India Act, 1955.
- (5) A copy of the Insurance Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and other members) Amendment Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.650(E) in Gazette of India dated 21st October, 2024 under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH):
Hon. Chairperson, Sir, with your permission, I rise to lay on the Table :-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986:-
 - (i) The Battery Waste Management (Amendment) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.190(E) in Gazette of India dated 14th March, 2024.
 - (ii) The Battery Waste Management (Second Amendment) Rules, 2024 published in Notification No. S.O.2374(E) in Gazette of India dated 20th June, 2024.
 - (iii) The Green Credit Rules, 2023 published in Notification No. S.O.4458(E) in Gazette of India dated 12th October, 2023.
- (2) A copy of the Notification No. S.O.05(E) (Hindi and English Versions) published in Gazette of India dated 1st January, 2024, making certain amendments in the Notification No. S.O.5481(E) dated 31st December, 2021 issued under Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986.

- (3) A copy of the Notification No. S.O.884(E) (Hindi and English Versions) published in Gazette of India dated 22nd February, 2024 notifying the methodology for calculating the green credit in respect of any activity undertaken under the Green Credit Rules, 2023, issued under sub-rule(1) of rule 5 of the said Rules.
- (4)
 - (i) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority, New Delhi, for the years 2018-2019 to 2022-2023 alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority, New Delhi, for the year 2018-2019 to 2022-2023.
- (5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.
- (6)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Biodiversity Authority, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Biodiversity Authority, New Delhi, for the year 2023-2024.
- (7) A copy of the Biological Diversity Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.665(E) in Gazette of India dated 25th October, 2024 under sub-section (3) of Section 62 of the Biological Diversity Act, 2002.
- (8) A copy of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.582(E) in Gazette of India dated 20th September, 2024 under sub-section (2) of Section 4 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE): Hon. Chairperson, Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table a copy of each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Output Outcome Monitoring Framework of the Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs and Sports for the year 2024-2025.
- (2) Output Outcome Monitoring Framework of the Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports for the year 2024-2025.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI SUKANTA MAJUMDAR): Hon. Chairperson, Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

- (1)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Haryana, Mahendergarh, for the year 2022-2023.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Haryana, Mahendergarh, for the year 2022-2023, together with Audit report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Haryana, Mahendergarh, for the year 2022-2023.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the University of Hyderabad, Hyderabad, for the year 2022-2023.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the University of Hyderabad, Hyderabad, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the University of Hyderabad, Hyderabad, for the year 2022-2023.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.
- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the University of Allahabad, Prayagraj, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the University of Allahabad, Prayagraj, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the University of Allahabad, Prayagraj, for the year 2022-2023.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI HARSH MALHOTRA): Hon. Chairperson, Sir, I beg to lay on the Table: -

- (1) A copy of the Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.475(E) in Gazette of India dated 5th August, 2024, under sub-section (3) of Section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.
- (2) A copy of the Companies (Adjudication of Penalties) Amendment Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.476(E) in Gazette of India dated 5th August, 2024 sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013.

... (*Interruptions*)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) : माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

- (1) अधिसूचना संख्या का.आ. 3959 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 18 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत जारी दिनांक 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (2) (एक) केंद्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केंद्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL
HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI GEORGE KURIAN): Hon. Chairperson,
Sir, with your permission, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Haj Committee of India, Mumbai, for the year 2022-2023.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Haj Committee of India, Mumbai for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.
- (iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Haj Committee of India, Mumbai, for the year 2022-2023.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

... (Interruptions)

ASSENT TO BILLS

1204 hours

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table the following 3 Bills passed by the Houses of Parliament during the Second Session of Eighteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 27th June, 2024: -

- I. The Jammu and Kashmir Appropriation (No.3) Bill, 2024
- II. The Appropriation (No.2) Bill, 2024
- III. The Finance (No.2) Bill, 2024

... (Interruptions)

(1205/KN/PS)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शङ्कीया) : आइटम नंबर 14. डॉ. फगन सिंह कुलस्ते जी – उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अनन्त नायक।

... (व्यवधान)

समितियों के लिए निर्वाचन

(i) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, श्री कृष्ण लाल पंवार, जिन्होंने 14 अक्टूबर, 2024 से राज्य सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के समाप्त न हुए भाग के लिए, समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, श्री कृष्ण लाल पंवार, जिन्होंने 14 अक्टूबर, 2024 से राज्य सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के समाप्त न हुए भाग के लिए, समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, श्री बीडा मस्थान राव यादव, जिन्होंने 29.08.2024 से राज्य सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के समाप्त न हुए भाग के लिए, समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से एक सदस्य निर्वाचित करे और समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, श्री बीडा मस्थान राव यादव, जिन्होंने 29.08.2024 से राज्य सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल के समाप्त न हुए भाग के लिए, समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से एक सदस्य निर्वाचित करे और समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

**(iii) Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology,
Trivandrum**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY; AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Hon. Chairperson, Sir, with your kind permission, I rise to move the following:-

“That in pursuance of sub-section (j) of Section 5 read with sub-section (1) and (2) of Section 6 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Act 1980, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Institute Body of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum subject to the other provisions of the said Act and the Rules and Regulations made thereunder.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (अ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अध्याधीन श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के संस्थान निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1208 बजे

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

Re: Need to address the problems in operation of Telephone Exchange in Karwar SSA in Uttara Kannada Parliamentary Constituency

SHRI VISHWESHWAR HEGDE KAGERI (UTTARA KANNADA): My Parliamentary Constituency is situated near Western Ghat region in Karnataka and many telephone exchanges in Karwar SSA in my Parliamentary Constituency are going down within a few minutes of power failure as installed battery sets are not taking load and battery reading comes down to below 47V within a minute. In this regard, attempts to install good quality 2 or more battery sets for the purpose were made having consultation with the officer in-charge of concerned telephone exchange. But still the same problem persists and due to non-installation of proper battery backup, it leads to problems in operation of transmission equipments, Mobile BTS equipments, and Exchange equipments. There is requirement of power plant in Karwar SSA as many Exchanges in Karwar SSA are going down due to lack of power plant modules and the installed batteries are not being charged up properly due to fault of power plant. So, many transmission equipments, mobile BTS equipments and Exchange equipments are also going down. In this regard, I urge the Minister of Communications to give the direction to the concerned authority to consider the issue and take action on urgent basis.

(ends)

Re: Need to bring a legislation on National Blood Transfusion to regulate and monitor blood transfusion services

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Over 1 million citizens in India require blood transfusions every month, yet many face significant challenges in accessing safe and timely blood supplies. Despite existing guidelines in the National Blood Policy (2002), hospitals often abdicate responsibility for sourcing blood, placing an undue burden on patients' families to organize blood donations. This situation has created a breeding ground for unethical practices, such as paid blood donations, and undermines patient safety. The need for a comprehensive legislative framework was emphasized in a 1996 Supreme Court ruling and is further supported by the World Health Organization. Although the National Blood Policy was established over 20 years ago, its implementation has been poor, leading to a fragmented blood transfusion system across various Government bodies. A National Blood Transfusion Act would streamline efforts to regulate and monitor blood services, ensuring consistent standards of safety, availability, and quality. This Act would empower a Central National Blood Transfusion Authority to set guidelines, regulate blood banks, ensure proper licensing, and enforce safety monitoring. It would also provide essential training, foster research, and improve coordination across healthcare institutions. I urge the Government to prioritize the creation of this Act to safeguard public health and ensure equitable access to safe blood transfusion services across the nation. (ends)

Re: Need to grant classical language status to Maithili Language

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा) : मैथिली भाषा की एक समृद्ध लिपि परम्परा है और करोड़ों लोगों की मातृभाषा है। यहां तक कि झारखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा मैथिली है। 2003 में परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने मैथिली भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करके इस भाषा की महत्ता को स्वीकार किया है। आज मैथिली भाषा ना केवल शिक्षा का माध्यम है अपितु शासन और प्रशासन की भी भाषा है। मैथिली भाषा शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने हेतु सभी मापदंडों को पूर्ण करती है। इस भाषा की प्राचीन साहित्यिक विरासत है, यह भाषा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। इस की अपनी भाषाई स्वतंत्रता है और इसका अपना ऐतिहासिक महत्त्व है। मैथिली भाषा का इतिहास अति प्राचीन है जो ऋग्वेद युगीन काल तक जाता है। मेरी माननीय गृहमंत्री जी से मांग है कि मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाय और जिससे भाषाई एवं सांस्कृतिक विरासत का सम्मान, संरक्षण एवं संवर्धन होगा और साथ-साथ करोड़ों मिथिलावासियों को गौरवान्वित महसूस होने का अवसर प्राप्त होगा।

(इति)

Re: Implementation of PM Surya Ghar Yojana in Bundelkhand, Uttar Pradesh

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): The PM Surya Ghar Yojana promises to transform the Bundelkhand region, including Jhansi, by harnessing the area's abundant sunlight. This initiative leverages the unique advantage of extended daylight hours in the region, making it an ideal area for solar power generation. By enabling households to install solar panels, the scheme aims to reduce electricity costs and ultimately provide free electricity to residents, significantly easing the financial burden on families in this economically disadvantaged area. Bundelkhand has long faced challenges of limited development and financial constraints, but with the Surya Ghar Yojana, residents have a promising opportunity to move towards energy independence. Access to free, sustainable electricity can empower local industries, agriculture, and households fostering overall economic growth. Additionally, the program promotes environmental sustainability by reducing reliance on traditional, non-renewable energy sources. In the long run, the PM Surya Ghar Yojana stands as a beacon of hope for Bundelkhand's revival, addressing both energy needs and economic disparities, and ensuring that even the remotest parts of the country benefit from renewable energy advancements. With the sun shining late into the evening, Jhansi and the Bundelkhand region can now look forward to a brighter and more prosperous future. (ends)

Re: Need to expedite implementation of Patmada Pump Canal Project in East Singhbhum District

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : मैं इस सदन में पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा, बोड़ाम और काटिन प्रखंड के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूँ। 2021 में झारखंड राज्य के जल संसाधन विभाग ने इन क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए पटमदा पम्प नहर योजना को मंजूरी दी थी। इसके बावजूद अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस योजना के लिए कंसल्टेंट द्वारा पिछले एक वर्ष में सर्वेक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा चुकी है, लेकिन जल संसाधन विभाग ने अब तक इसे स्वीकृति नहीं दी है। इस विलंब के कारण लगभग 12,500 हेक्टेयर भूमि में किसानों को सिंचाई सुविधा से वंचित रहना पड़ा है, जो उनकी कृषि उत्पादन को प्रभावित कर रहा है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि सिंचाई की सुविधा से न केवल किसानों की खेती में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्रीय कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस काम में की गई देरी पर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों को शीघ्र ही आवश्यक सिंचाई सुविधाएँ मिल सकें और इस योजना की मंजूरी के लिए शीघ्र निर्णय लिया जाए। (इति)

Re: Need to include Sambalpur / Kosali language in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री प्रदीप पुरोहित (बारगढ़): मैं माननीय गृहमंत्री का ध्यान संविधान की आठवीं अनुसूची में संबलपुरी/कोसली भाषा को शामिल करने और इसे ओडिशा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ओडिशा के 30 में से 11 जिलों में लगभग दो करोड़ लोग संबलपुरी/कोसली भाषा बोलते हैं। यह एक प्राचीन भाषा है, जो समृद्ध मौखिक परंपरा और साहित्यिक विरासत से परिपूर्ण है। इसमें रामायण, महाभारत और भगवत गीता के अद्भुत रूपांतरण समेत अनेक साहित्यिक कृतियां शामिल हैं। प्रतिष्ठित लोककवि पद्मश्री हलधा नाग, प्रसिद्ध गीतकार श्री मित्रभानु गौंटिया, और प्रतिभाशाली संगीतकार जितेंद्र हरिपाल जैसे व्यक्तित्व इस भाषा और संस्कृति की गहराई और गौरव को दर्शाते हैं। संबलपुरी/कोसली पश्चिमी ओडिशा के लोगों की प्राथमिक भाषा है। 1 मार्च 2014 को ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से केंद्र सरकार से संबलपुरी/कोसली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया था। दुर्भाग्य से तत्कालीन राज्य सरकार ने इस मामले को उतनी तत्परता से आगे नहीं बढ़ाई जितनी तत्परता से सभी को संबलपुरी/कोसली को आधिकारिक राज्य भाषा के रूप में मान्यता देनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि संबलपुरी/कोसली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल के साथ ओडिशा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

(इति)

Re: Need to expedite establishment of Sainik School in Godda, Jharkhand

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): The overall condition of Education in Santhal Pargana region is a subject-matter of utter neglect in spite of the fact that since time immemorial, the entire region was considered to be a harbinger of ancient education practices and dissemination of social norms and mores. There has been a vociferous demand of establishing a Sainik School in Godda/Deoghar so that this area could also share the pride of having quality education to their children. In February 2016, the then Honorable Defence Minister, visited my constituency and after acknowledging the backwardness of the region, he was kind to announce setting up of a Sainik School in Godda/Deoghar. Further, as a consequence to the said announcement, the Project for establishing a Sainik School was immediately sanctioned by the Ministry of Defence. However, it is a matter of concern that since then, more than seven years have elapsed, but the entire Project has not witnessed any visible progress.

(ends)

Re: Poor financial health of Discoms in Delhi

श्री योगेन्द्र चांदोलिया (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): मैं आज दिल्ली के लोगों को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रीय राजधानी की बिजली आपूर्ति का प्रबंधन तीन कंपनियों द्वारा किया जाता है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड। जबकि टीपीडीडीएल लाभ में चल रही है, अन्य दो कंपनी 26,000 करोड़ रुपये के घाटे में हैं जबकि पूरी दिल्ली में बिजली की दरें तीनों कंपनियों की समान हैं। यह चौंका देने वाला घाटा न केवल दिल्ली के बिजली क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता को खतरे में डालता है, बल्कि नागरिकों पर एक समान बिजली दरों का बोझ भी डालता है। दिल्ली सरकार की कंपनियों से क्या शर्तें हैं जो उनके लाइसेंस रद्द नहीं किए गए? और दिल्ली सरकार के दो बिजली घरों को 26,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रहने के बावजूद उनके लाइसेंस का नवीनीकरण क्यों किया जा रहा है? इस स्थिति के परिणामस्वरूप दिल्ली के राजस्व में भारी नुकसान होता है। मैं आग्रह करता हूँ कि इसकी जाँच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कारवाई हो ताकि सार्वजनिक राजस्व की रक्षा की जाए। (इति)

Re: Augmentation of train services connecting Palamu Parliamentary Constituency

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे से संबंधित मांगों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ जो निम्नलिखित हैं:-

1. 12453/12454 रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नगर उंटारी (श्री बंशीधर नगर) रेलवे स्टेशन पर ठहरावा।
2. वन्दे भारत ट्रेन को रांची से डालटनगंज होते हुए वाराणसी तक चलाई जाए।
3. पटना-सिंगरौली एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 23347/23348 एवं शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 11447/11448 का मेराल रेलवे स्टेशन पर ठहरावा।
4. पलामू एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13347/13348 का रजहरा स्टेशन पर ठहरावा।
5. गरीब रथ ट्रेन संख्या 12877/12878 का मोहम्मदगंज पर ठहरावा।
6. रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12453/12454 वाया डालटनगंज होकर सप्ताह में 2 दिन चलती है, उसे चार दिन चलाई जाए।
7. रांची-नई दिल्ली गरीब रथ ट्रेन 12877/12878 को सप्ताह में तीन दिन चलती है उसे 6 दिन चलाई जाए।
8. रांची-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 18311/18611 रांची से वाराणसी तक चलती है उसे गोरखपुर तक विस्तारित किया जाए।
9. रांची से वाया डालटनगंज होकर गोरखपुर तक एक नई ट्रेन चलायी जाय, जो कोरोना काल में चली थी। उसे बंद कर दिया गया है पुनः चालू किया जाय। डालटनगंज से गोरखपुर जाने वाले यात्रियों की संख्या अत्यधिक है।

अतः महोदय उपरोक्त मांगों को पूरा कराने की कृपा करेंगे, ताकि यात्रियों का रेलवे की यात्रा सुगम हो सके। (इति)

Re: Need to implement stringent Banking Protocols and KYC Norms to curb cyber financial frauds

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Under PM Shri Narendra Modi Ji's visionary leadership, India has made significant progress in digital transformation. Today, I would like to draw the attention of the Hon'ble Home Minister and Finance Minister to an alarming issue of cyber financial frauds threatening our economy. Recent studies by the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) project potential losses of over ₹1.2 lakh crore in the next year, approximately 0.7% of our GDP. In just six months of 2024, reported losses have reached ₹11,269 crore, excluding unreported cases and direct police complaints. The situation is particularly concerning as most frauds originate from China and South-East Asian countries. Nearly 4,000 mule bank accounts are identified daily, with scam compounds operating from Cambodia, Myanmar, Laos, and Azerbaijan. Fraudulent withdrawals occur both domestically and internationally. The grave concern is the use of crypto currencies for money laundering, with ₹5.5 crore laundered through international exchanges in just three months. I urge the MHA and Finance Ministry to implement stricter banking protocols and KYC norms, enhance international cooperation, and create robust public awareness campaigns. This requires immediate intervention to protect our citizens' financial security and our economy. (ends)

Re: Alternate route for proposed expansion of Chandikhole-Paradip Section of NH-53 in Odisha

SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): The construction of National Highways (NH) touched to more than 30 Kms per day during the financial year 2023-24, and the network, which has increased by 60% from 91,287 km in 2014 to 1,46,145 km in year 2023. As part of this progress, the State of Odisha has also gained much during last 11 years. Recently, the work for the rehabilitation and upgradation from 4 to 8 lane of Chandikhole-Paradip section NH-53 has been awarded and is expected to be completed soon. However, this NH project will be acquiring land of two villages: Bijaychandrapur and Udaybat (around 2.5 km distance) and inhabitants of these two villages are going to be evicted. The villagers will be losing their home, shops and livelihoods. If an alternative route for the expansion of NH 53 on this 2.5 km stretch is readily available, and eviction of two villagers is avoidable without demolition of homes and shops, this may be considered instead of evicting families of these two villages. I would urge the Union Minister of Road Transport and Highways to look into the matter urgently and protect the interest of these two villagers in my Parliamentary Constituency-Jagatsinghpur, Odisha. (ends)

**Re: Need to enact the Constitution (Schedule Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019
for inclusion of six ethnic communities of Assam in the List of Schedule Tribes**

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Six ethnic communities in Assam namely the Adivasi/Tea Tribes, Tai Ahom, Moran, Matak, and Chutia Koch-Rajbongshi have been demanding their inclusion in the Central list of Scheduled Tribes. The demand is based on the argument that these communities possess the characteristics of Scheduled Tribes and face socio-economic disadvantages. The National Commission for Scheduled Tribes (NCST) has also approved their inclusion. The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019 was introduced in the Rajya Sabha on 8th January 2019. This bill sought to amend the list of Scheduled Tribes of Assam, specifically to include six ethnic communities: Adivasi/Tea Tribes, Tai Ahom, Moran, Matak, Chutia, and Koch-Rajbongshi. The delay in the enactment of this crucial legislation has had a profound and negative impact on these marginalized communities. They continue to suffer from socio-economic disparities, discrimination, and lack of adequate representation. The recognition as Scheduled Tribes would have provided them with much-needed constitutional safeguards, affirmative action, and access to Government schemes and resources. I urge the Government to prioritize this bill's passage and expedite the legislative process. The continued delay is causing immense hardship to these communities, and it is imperative to address their legitimate aspirations. (ends)

**Re: Need to establish a National Mission for Springshed Management along with
National Registry of Springs**

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAGAON): I rise today to talk of a slow-onset disaster in many hilly areas of the North East face. In recent years, several villages across the region have reported the drying up of their mountain springs. This is particularly alarming as many are wholly dependent on springs for water. For example, over half of Meghalaya's villages were dependent on springs and Sikkim too derives much of its drinking water from them. Springwater quality has been declining, according to a recent study on two springs in Tripura. Springs also contribute to the base flow of the region's great rivers, like the Brahmaputra, affecting those in the plains as well. A 2018 NITI Aayog Report stated that nearly half of the springs in the Indian Himalayas, many of which fall in the North East, had dried up or become seasonal due to development projects and climate change. I thus urge the Government to immediately establish a National Mission for Springshed Management, which can help states build capacity and integrate springshed management into development projects. A National Registry of springs must also be established to periodically monitor the health of springs and ensure a continuous supply of crucial data. (ends)

**Re: Need to expedite completion of Peddapalli-Manuguru railway line in
Manthani region of Peddapalli Parliamentary Constituency**

SHRI VAMSI KRISHNA GADDAM (PEDDAPALLE): I rise to bring attention to the concerns surrounding the Peddapalli-Manuguru railway line, which traverses the Manthani region within my constituency. Despite its designation as a 'special' project by the Centre, aimed at accelerating its progress, the survey remains incomplete, leaving the project in limbo. This ₹3,600 crore initiative is critical for the socio-economic development of the area, particularly benefiting the tribal population in the erstwhile Khammam district. The project promises direct rail connectivity to the national capital, improving accessibility and fostering growth. The railway line is vital for regions associated with the Singareni coal mines, as coal is currently transported via the Kazipet junction, incurring significant costs. The proposed line would reduce these expenses and enhance economic efficiency. However, delays in completing the survey and initiating construction hinder the realization of these benefits. It is imperative to clarify the funds allocated for the project this financial year and ensure their efficient utilization. Establishing a clear timeline for completing the survey and commencing construction is essential. Expediting the Peddapalli-Manuguru railway line will fulfill long-pending aspirations, bolster connectivity, and stimulate economic growth in the resource-rich Manthani region. (ends)

**Re: Need to convert existing Ayurveda Hospital at Ezhukone, Kerala to a full-
fledged Ayurveda Medical College**

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I wish to draw the attention of the Hon'ble Minister for Labour and Employment to the urgent need for improving healthcare and educational facilities in Ezhukone, Kollam, Kerala. The Ezhukone ESIC Hospital serves a vast population of insured workers and their families. However, it requires urgent upgradation to a 250-bed super-specialty allopathic hospital to meet the increasing demand for advanced medical care. Additionally, the dental and pharmacy courses earlier sanctioned for this institution must be reinstated to support healthcare education and skill development in the region. Furthermore, the existing Ayurveda Hospital in Ezhukone holds immense potential to transform into a full-fledged Ayurveda Medical College. Upgrading this facility would not only preserve and promote traditional medicine but also provide enhanced educational and research opportunities in the field of Ayurveda. I urge the Hon'ble Minister to prioritize these initiatives, ensuring improved healthcare services and educational facilities for the benefit of the region. (ends)

Re: Need to make available adequate quantity of DAP to farmers in Rajasthan

श्री राहुल कस्वां (चूरु) : देश में इस समय रबी फसल की बुवाई शुरू हो चुकी है व देश भर में किसानों को इस समय भारी मात्रा में DAP की आवश्यकता है, जिसके कारण राजस्थान के किसानों के द्वारा DAP की काफी मांग की जा रही है, लेकिन मांग के अनुरूप पिछले अक्टूबर महीने से ही DAP उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में DAP की काफी ज्यादा किल्लत चल रही है। मेरे लोकसभा क्षेत्र चूरु में 12 हजार टन DAP की मांग विभाग द्वारा राज्य सरकार को भिजवाई गई थी लेकिन उसके एवज में 6 हजार टन DAP ही उपलब्ध करवाई गई है। भारत सरकार के द्वारा प्रचुर मात्रा में DAP राज्य सरकार को उपलब्ध करवाए जाने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा कृत्रिम कमी बताते हुए किसानों को उचित मात्रा में DAP उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है जिसके कारण चूरु लोकसभा क्षेत्र सहित राज्य के किसानों में रोष व्याप्त है, और जगह जगह धरने प्रदर्शन आदि किये जा रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए राज्य के किसानों को उचित मात्रा में DAP उपलब्ध करवाई जावे ताकि रबी फसल की बुवाई की जा सके। (इति)

Re: Situation arising out of merger of Ananthpuri FM with Akashvani AM

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I wish to draw the Hon'ble Minister's attention to the unfortunate consequences of the merger of Ananthpuri FM with Akashvani AM, which has caused anguish to innumerable Keralites since late July 2023. Apart from the grievances of 4.5 million listeners, many of whom grew up tuning into Ananthpuri FM every morning, the merger rendered numerous staff members unemployed, plunging them into financial and emotional turmoil. Especially affected were the casual staff between the ages of forty and sixty who, owing to age and limited employment prospects, have been struggling to find new livelihoods. Every month Ananthpuri FM employed around a hundred part-time anchors, several among them being women who are also single parents. These anchors hosted 5-6 programmes every month, making their stints at Ananthpuri a vital stream of income. That an FM channel which was immensely popular and generated a yearly revenue of 1.5 crores, and which embodied the popular and literary culture of Kerala, should have thus been dismantled is regrettable. I also wonder why the option of instituting a separate FM transmitter for Ananthpuri was not explored. I urge the Minister to take swift action to address the hardships faced by those who have lost their jobs due to the merger and those who can no longer enjoy a beloved and widely-heard radio channel. (ends)

Re: Need to improve rail connectivity to Mau District, Uttar Pradesh

श्री राजीव राय (घोसी) : मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जिला मऊ की जनता की परेशानियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मऊ के अधिकांश लोग हैंडलूम एवं पावरलूम के कारोबार से जुड़े हुए हैं। कारोबार के सिलसिले में उन्हें मऊ से दक्षिण भारत के अनेक क्षेत्रों, उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों एवं दिल्ली और मुम्बई जाना पड़ता है, लेकिन पर्याप्त ट्रेन सेवा न होने के कारण उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित होता है और उन्हें आर्थिक हानि भी होती है। मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि जिला मऊ के हैंडलूम एवं पावरलूम कारोबारियों को पर्याप्त ट्रेन सेवा न होने के कारण बड़े व्यावसायिक क्षेत्रों से संपर्क बिगड़ता जा रहा है, जिससे कठोर परिश्रम करने के बावजूद उनकी माली हालत बिगड़ती ही जा रही है।

अतः मैं सरकार से पुरजोर अपील करता हूँ कि मऊ स्टेशन से एक नई ट्रेन दक्षिण भारत के लिए और मऊ स्टेशन से एक वन्दे भारत ट्रेन दिल्ली एवं मुम्बई के लिए शीघ्रताशीघ्र आरम्भ की जाये। साथ ही लोकमान्य तिलक ट्रेन जो मुम्बई तक जाती है, को साप्ताहिक के स्थान पर प्रतिदिन चलाया जाए। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जो गाजीपुर-बलिया तक जाती है, को मऊ रेलवे स्टेशन तक चलाया जाए।

महोदय, मऊ हैंडलूम एवं पावरलूम के कारोबारियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए दोहरीघाट रेलवे स्टेशन से एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को प्रयागराज रेलवे स्टेशन तक चलाया जाए। (इति)

Re: Need to improve healthcare facilities in Etah Parliamentary Constituency

श्री देवेश शाक्य (एटा) : मेरी लोक सभा एटा, कासगंज के अन्तर्गत आने वाले मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल, सी० एच० सी० पी० एच० सी० पर डाक्टरों के पदों से भी आधे डाक्टर वर्तमान में स्थायी तौर पर है। जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रूप से नहीं चल पा रही है। लोगों को इलाज के लिये अलीगढ़ और आगरा जाना पड़ता है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन रिक्त पदों को स्थायी रूप से कब तक भरा जायेगा जिससे मरीजों को सुचारु रूप से इलाज मिल सके। रात्रि की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है। एटा मेडिकल कालेज में एम० आर० आई० की व्यवस्था और आपरेटर नहीं है। कब तक इस व्यवस्था को पूर्ण किया जायेगा। एटा कासगंज की जनता को प्राइवेट लैबों में जाना पड़ता है, जिससे पीडित परिवारों पर आधिक बोझ पड़ता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि एटा कासगंज में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिये जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने का कष्ट करे। (इति)

Re: Need to expedite construction of Railway line project between Tindivanam and Nagari in Tamil Nadu

SHRI THARANIVENTHAN M. S. (ARANI): I would like to draw the attention of the Government regarding the need to expedite the long-delayed construction work of 196 kms railway line project between Tindivanam and Nagari which were announced in 2010 by the then Hon'ble Minister of Railways. The then Government had allocated Rs. 600 crore for this work. However, Rs. 192 crore has already been given by the Government to those who have given their land i.e. agricultural land covering 33 villages belonging to Vandavasi Seiyaru Arani taluks starting from S Kateri village in the Wayyora Arani Parliamentary Constituency in Tiruvannamalai district to Arani Irumpedu village for the construction of the railway line. This project was allocated limits Rs 350 crore in the Union Government's recent interim budget and Rs 200 crore last year. The Tamil Nadu Government has paid special attention to this and has excavated the land where the track is to be built and handed it over to the Railway department. In the funds allocated for this purpose, 75 percent of work of constructing flyovers on rivers including Suga Nadi Seyyar Balaru in the areas of Vandavasi Seyyar Ranipet Arcot is completed. Hence, I request the Hon'ble Minister of Railways, in the interest of the general public of Arni district.

(ends)

Re: Need for investing in in-depth agricultural research in Andhra Pradesh

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in its first advance estimates has predicted a record Kharif harvest of 1,647.05 lakh metric tonnes. However, as we secure food for our nation, we must also prioritise its nutritional value. A recent ICAR study highlights a concerning trend: high-yielding varieties of rice and wheat have significantly reduced micronutrient densities, with zinc levels dropping by up to 33% in rice and 30% in wheat, and iron levels similarly declining. To achieve nutrition security, it is time to shift our focus from yield per hectare and lakh metric tonnes to nutritional output per hectare. We must promote crop diversity and introduce new metrics like an agriculture income diversity score and incentivize farmers accordingly. Indicators like soil organic carbon must be included in the soil health card. Other metrics such as landscape diversity scores, soil biological activity, and water-use efficiency must be mainstreamed into agricultural practices. I propose investing in in-depth agricultural research, particularly in Andhra Pradesh, the rice bowl of India and home to Acharya N.G. Ranga Agricultural University. On the 125th anniversary of the legendary Rythu Ranga, let us honour his vision by driving innovation that ensures doubling of farmer income and sustainable agriculture.

(ends)

Re: Need to curb unethical practices of Private Finance Companies in the country

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : देश भर में कई निजी वित्तीय कंपनियां (पीएफसी) व्यक्तिगत और व्यावसायिक लोन प्रदान करती हैं, लेकिन इन पर सरकारी नियंत्रण की कमी के कारण ये कंपनियां ग्राहकों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करती हैं। समय पर किस्त न देने पर कुछ पीएफसी आक्रामक और बलपूर्वक तरीके अपनाते हैं, जैसे बार-बार कॉल करना, धमकाना, और सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना। वसूली एजेंट उधारकर्ताओं के रिश्तेदारों से संपर्क कर पुनर्भुगतान के लिए दबाव बनाते हैं, और कभी-कभी शारीरिक धमकी या हिंसा का सहारा लेते हैं। इसके अलावा, पीएफसी अक्सर लागू शुल्कों और ब्याज दरों का पहले से खुलासा नहीं करते, जिससे ग्राहकों पर अप्रत्याशित वित्तीय बोझ पड़ता है। कई कंपनियां भ्रामक जानकारी देकर ग्राहकों को प्रतिकूल शर्तों में फंसा देती हैं। बिना सहमति के ग्राहक डेटा को तीसरे पक्ष के साथ साझा करना भी एक गंभीर समस्या है, जो गोपनीयता का उल्लंघन और धोखाधड़ी का जोखिम बढ़ाता है। अतः, सरकार को इन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

(इति)

Re: Need to redevelop Railway Mechanical Workshop, establish an electric Loco shed and a new workshop for LHB maintenance in Samastipur Parliamentary Constituency

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : मेरा संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर मेधावी और परिश्रमी युवाओं की भूमि है, लेकिन संसाधनों की कमी और औद्योगिक विकास के अभाव में यह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। रोजगार की कमी के कारण यहाँ के युवा देश के अन्य हिस्सों में पलायन करने को मजबूर हैं, जहाँ उन्हें क्षेत्रीय भेदभाव और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्तीपुर, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म और कर्मभूमि है। उन्होंने सामाजिक असमानता को समाप्त कर एक समतामूलक समाज के निर्माण का सपना देखा था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके अतुलनीय योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर सच्ची श्रद्धांजलि दी। उनका सपना अभी अधूरा है, क्योंकि हमारा समाज अब भी पूर्ण समानता की ओर अग्रसर नहीं हुआ है। समस्तीपुर का विशाल रेलवे नेटवर्क इस क्षेत्र के औद्योगिकरण और विकास की बड़ी संभावनाएं प्रदान करता है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करती हूँ कि समस्तीपुर रेल मंडल के यांत्रिक कारखाने का नवीनीकरण किया जाए, विद्युत लोको शेड शुरू किया जाए और एलएचबी मेंटेनेंस के लिए नया कारखाना स्थापित किया जाए। इससे युवाओं को स्थानीय रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, और रेलवे राजस्व में वृद्धि होगी।

(इति)

Re: Need to establish an AIIMS in Baghpat Parliamentary Constituency

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बागपत की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत गंभीर है। क्षेत्र के नागरिकों को उचित और समय पर चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। यहाँ मामूली बीमारियों के लिए लोगों को मेरठ, दिल्ली जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। बागपत में विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की कमी के कारण जनता को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए स्थिति और भी अधिक विकट है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ बेहद दयनीय हैं, और सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि बागपत में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए अविलंब आवश्यक कदम उठाए जाएँ। हमारे क्षेत्र में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की स्थापना की जाए। AIIMS का होना न केवल हमारे क्षेत्र के नागरिकों को उत्तम चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और क्षेत्र का समग्र विकास होगा। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर शीघ्रता से विचार करेगी और बागपत के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

(इति)

Re: Rise in prices of food items

SHRI AMRA RAM (SIKAR): In September this year average price rise hit a nine-month high of 5.5 per cent. More significantly prices of food items crossed 9.2 per cent. A majority of Indians spend nearly half of their income on food. So, food inflation hurts the most. Among food items, vegetables in particular saw a staggering price rise with year-on-year price increases of 42.4 per cent for tomatoes, 66.2 per cent for onions, and 65.3 per cent for potatoes. These three are the most consumed vegetables, across the country. While the Government cites usual reasons of weather disruptions, the fact remains that every year, prices of some vegetables undergo an unbearable spike that has the effect of transferring crores of rupees from already strained family budgets to the coffers of big traders and wholesalers. Several other items of consumption too are seeing exorbitant price rise. One of them is cooking oils, which is partly attributable to the rise in crude palm oil prices by over 45 per cent in the past three months. Crude palm oil is used not only for processed food items but also for items like soaps and cosmetics.

(ends)

**Re: Increasing incidents of human-wildlife conflict in Bodoland
Territorial Region in Kokrajhar Parliamentary Constituency**

SHRI JOYANTA BASUMATARY (KOKRAJHAR): I would like to draw the urgent kind attention of Union Government on the regular human - wildlife conflicts in Bodoland Territorial Region (BTR) in my Kokrajhar Parliamentary Constituency. Manas Nation Park (MNP) falls within the territorial domain of BTR and it is part of the larger MTR which covers an area of 2,837 sq km. The park in India shares its international border with Bhutan's Royal Manas National Park. Together these two Protected Areas form the Manas landscape. Every year increasing incidents of wild animal attacks on the villages have affected the people as well the biodiversity of the area. Illegal poaching and tree cutting is also few of the major problems which need to be addressed. I, therefore, request the Union Government to look into the matter and take necessary action on illegal poaching and take measures to control elephants attack on villages.

(ends)

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज आप सब बैठिये। आप सदन को चलने दीजिए। आपकी बात भी सुनी जाएगी। आपको भी पूरा मौका मिलेगा। प्लीज आप सब बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर बैठिये। सदन को चलने दीजिए। सदन का महत्वपूर्ण समय है। पूरा देश देख रहा है। प्लीज आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 28 नवंबर, 2024 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1209 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 28 नवम्बर 2024/7 अग्रहायण 1946 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।